(सभी आकंड़े निवल मि०यू० में)

	पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय परियोजनाओं के नाम	अप्रैल, 95 से जनवरी, 96 तक	
		हकदारी	वस्तुतः प्राप्त
1.	कोरबा एसटीपीएस	2672.2	3512.1
2.	विंध्याचल एसटीपीएस	1861.5	2068.6
3.	कवास गैस	566.7	467.2
4.	गंधार गैस	817.7	558.9
5.	तारापुर एपीएस	625.6	625.6
6.	ककरापाड़ एपीएस	618.6	496.7
	जोड़	7162.3	7729.1

उपरोक्त के अलावा गुजरात ने पड़ौसी उत्तरी क्षेत्र से 107.7 मिलियन यूनिट तक की सहायता प्राप्त की है।

(ख) यद्यपि, क्षेत्र में राज्यों को केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों से सहमत फार्मूले के अनुसार विद्युत का आवंटन किया जाता है, तथापि, एकीकृत ग्रिड प्रचालन में राज्य कभी-कभी अपने हिस्से से अधिक अथवा कम विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच इस प्रकार के अन्तःक्षेत्रीय विद्युत अंतरण के लिए टैरिफ के बारे में इनके बीच विपक्षीय रूप से सहमति होती है।

((ग) 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली गुजरात की कोई भी विद्युत परियोजना जिसके निवेश के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किए जाने की सिफारिश की गई हो, ऐसी कोई परियोजना योजना आयोग में लम्बित नहीं है। विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया है, जिसकी अनुपालना किए जाने पर अपेक्षित स्वीकृति समयबद्ध रूप से प्रदान की जाती है। चार परियोजनाओं, यथा जी पी सी एस की सोगा लिग्नाइट और खारसलिया लिग्नाइट, जीईबी की गुजरात तटीय परियोजना और एनटीपीसी की कवास-2 परियोजना के लिए इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

हथकरघा और विद्युतकरघा एककों का बंद किया जाना

100. **श्री अजीत जोगी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित मूल्यों पर सूती धागा उपलब्ध न होने के कारण विद्युत से हथकरघा और विद्युतकरघा एकक धीरे-धीरे बंद होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में आज तक बंद किये गये ऐसे एककों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में सूती की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने इसके आयात में कोई छूट देने की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूती धागे के निर्यात पर प्रतिबंध न लगाए जाने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी नहीं। हथकरघा और विद्युतकरघा एककों की अर्थ क्षमता अनेक कारकों पर निर्भर करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बन्द पड़े एककों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सूती यार्न का आयात ओ जी एल के अन्तर्गत है।

(घ) सूती यार्न का निर्यात विनियमित होता है तथा हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों के हितों को ध्यान में

रखते हुए घरेलू मांग, उपलब्धता तथा कीमतों का मूल्यांकन करने के बाद कोटा रिलीज किया जाता है।

कम्पनियों द्वारा कर की चोरी

101. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1996 के हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, नई दिल्ली में "करोड़ों रुपये की कर चोरी कर रही हैं भारतीय कम्पनियां" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान की गई कर की चोरी का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Existing credit curbs on industries

102. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the industrialists have recently requested for easing the existing credit curbs on the industry; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI-PROSAD PAL): (a) and (b) It is not clear from the Question as to which credit curbs on industries the Hon'ble Member has referred to. However, the Reserve Bank of India (RBI) has reported that sanction of bridge loans by banks and financial institutions against public issues had been prohibited and continues to be so because at the moment there does not seem to be a risk-free arrangement possible for these advances, which are mostly in the form of unsecured credit. RBI has also advised the banks on December 1, 1995 that repayment of bank credit for imports will not be permitted before expiry of one month from the date of disbursement/ drawal of import finance.

NTC Units in Punjab

103. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of units of NTC that are functioning in Punjab; and

(b) the number of such units which are likely to be set up in that State during the next two years?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) There are 4 nationlised textile mills in Punjab under the NTC (DP&R) Ltd. There is no proposal to set up any new unit in Punjab during the next two years.

Self-assessment by tax payers

104. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Governmet have initiated measures to encourage self-assessment by tax payers on their income;

(b) whether any projects have been implemented to improve image of Income Tax Department; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) As per Section 140A of Income-tax Act, 1961 if any tax is payable on the basis of any return required to be furnished after taking into account the amount of tax, if